

ance to anybody who goes and encroaches on Government land and claims all those facilities which we have given to these people when they are asked to evict. We want to avoid that precedent because, after all, they are encroaching on Government land which is not authorised. If we treat it as a precedent, then people will start on encroaching on Government land. Because, in Kerala land is very limited. So, if anybody goes and occupies a forest land we are asked to give the same treatment when they are evicted, it will be rather difficult. But, in this case, having regard to the fact that they have been there since 1942, I am not taking that attitude.

Shri Vasudevan Nair: The Government sent them there.

Shri Hathi: Whatever it be, I am not taking that legal or technical stand. So far as free ration is concerned, we have given them Rs. 25 extra. Regarding dispensaries, we have already directed a medical officer to visit the area daily and, if it is not possible, on alternate days. Then, I shall instruct the Kerala Government that, if possible, some works may be opened so that they may get employment. I think these are the main demands.

I am sorry, in the question he simply asked whether Government are aware of the sufferings of those people. I said "yes". If he had asked what their demands were etc. I would have given the information, because I do not want to hide anything from him or from the House. But the question was whether the Government is aware of this and so I said "yes". We have received representation and we would have given the details if they had been asked for. As these are the difficulties that have been experienced by them I would certainly look into them. I will also look into the question of giving them some employment.

One of the items which I find here is that three wells are sanctioned. If instead of three more wells are necessary I will ask them to have five wells, because these are the facilities

which we have to look into from the humanitarian point of view.

17:28 hrs.

MOTIONS RE: (i) FOOD SITUATION AND (ii) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS--contd.

श्री सुतजीवास जाधव (भादेइ) :
 उपायगल महोदय, यहां पर दो दिनों से जो विब्रेट हो रहा है वह देश के बन्दर प्रकाश पड़ने से जो तकलीफ हो रही है उसके लिये हो रहा है। मैं जहां से घाया हूं, यद्यपि महाराष्ट्र में खरीफ धौर रबी के लिये बरसात न होने से दिक्कत पैदा हो रही है। एक तो वहां धनाज की दिक्कत है उसके साथ ही पीने के लिये पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है, जानवरों का खारा भी नहीं मिल रहा है। यह ठीक है कि बरसात का पानी हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में बरसात का लाना या भन्द करना नहीं है। लेकिन जिस नदी में पानी होता है हर वक्त वहां से पानी पीने के लिये हम नहीं जाते हैं। वहां से घड़े घर कर घर में ला कर रखते हैं और एक दो दिन इस का इस्तेमाल करते हैं।

17:29 hrs.

[**SHRI SONAYANE in the Chair**]

उसी तरह से जब जब बरसात हो रही थी ईम्स वगैरह तैयार कर के हम को पानी सम्भाल कर रखना बाहिस या धौर वसियत बनौह कर के इस्तेमाल करना चाहिये था। लेकिन वह शुरू से लेकर मत्तरह कहीं में बितना होगा या नहीं हुआ। और उसका मतीबा यह हुआ है कि हमारे यहाँ सिंचाई नहीं हो सकी।

इसके साथ साथ हम धमरीका से जो धनाज पैगवते थे उसका भी बहुत भारी परिणाम उत्पादन पर पड़ा है। चूंकि धनाज पैदा करने वाले को उस को कीमत पूरी नहीं मिल रही है इस लिये वह कंज क्राप की धौर बला गया और कंज क्राप के होने से धनाज कम हुआ। इस के बन्दर वह भी एक केंटर है।

[श्री तुलगी दास जाधव]

तो !;सीलिए जो पहले बातें हुईं, जिस बाबत में शपनी गलती हुई वह सुधारने का एक मौका है। अभी इस वक्त यह प्रकाश पड़ने से जो तरीके या जो प्रयत्न करने हैं वह ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि जिससे भागे कभी ऐसा मौका भा जाय कि बरसात न हो तो भी शपने को तकलीफ न हो।

अभी मैं महाराष्ट्र की बात कहता हूँ। वहाँ 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन में से एक दो डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया जाय तो महाराष्ट्र में बड़ी दिक्कत और बड़ा धोखा है। इस समय 1 ह 12 रुपये और 12 सी रुपये के जानवर की कीमत बाजार में 100 रुपये या 200 रुपये तक है और वह भी खरीदी करने वाले जो लोग हैं वह कसाई लोग हैं। मैंने अभी चार दिन पहले भोलापुर में देखा तो वहाँ बकरी का या भेड़ का या मुर्गी का जो मांस है उसकी कीमत 4 रुपये और 3 रुपये सेर है लेकिन जानवरों के मांस की कीमत 1 रुपये और 12 घाने हो गई है। इसके माने यह है कि ये सब जानवर कट रहे हैं और यह ज्यादा कटने के बाद अगले मौसम के लिए जानवर मिलने मुश्किल हैं। इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी करें, कि जल्दी से जल्दी जानवरों को सम्हालने की कोशिश करें।

दूसरी बात—आज महाराष्ट्र के बाजार जो ज्वारी का एरिया है, उसमें तो ज्वारी का भाव डेढ़ रुपये से 2 रुपये किलो तक है और बाजरे का भी सवा रुपये से डेढ़ रुपये किलो तक है। गेहूँ तो दो रुपये से ढाई रुपये तक है और जो खाद्य तेल है सरसों का उसका

भाव 4 रुपये किलो तक है। सीरिअल्स जो हैं उनका भी दाम डेढ़ रुपये किलो है। आजकल जो वहाँ लोग काम करने जाते हैं वह वैसे पर नहीं जाते हैं, वह तो कहते हैं कि हम को भनाज दीजिये तब हम काम पर जायेंगे। काश्तकार के काम के लिए वह नहीं जाते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि किसी भी हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट को महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा भनाज देने की कोशिश करनी चाहिए। देश में गये हुए सोलह सत्रह वर्षों में 40 परसेंट खेती का उत्पादन बढ़ गया है और 35 करोड़ से 47 करोड़ तक लोक संख्या बढ़ गई, रोजाना पचास हजार लोग बढ़ते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ गई, यह सब काल में रख कर गवर्नमेंट का काम था कि पिछले सत्रह वर्षों में या दस बारह वर्षों में भनाज की इस रीति से बढ़ती करे जिससे उसकी कमी न पड़े। लेकिन वह भनाज की बढ़ती करने वाले जो काश्तकार हैं, मेरी यह राय है और मैंने बहुत दफा बोलते हुए कहा कि काश्तकारों की तरफ जिस रीति से देखने की गरज थी उस रीति से देखा नहीं। छोटे छोटे जो धन्धे हैं उनके अन्दर जो बंपिटल है, जो भंडार हैं, उसमें कभी किसी धन्धे के अन्दर अग्रर कभी मनाफा न हो तो धन्धा बन्द हो जाता है। इसी रीति से अग्रर काश्तकारी का जो धन्धा है, खेती का धन्धा है उसको देखा जाय तो उसमें हमेशा वह नुकसान में है और सरकार ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी तो यह राय है कि इस वक्त सरकार को ऐसी योजना करनी चाहिए कि जिससे काश्तकार खेती को एक बड़ा धन्धा समझ कर उसके पीछे पड़े और काश्तकार को जो कचहरी वगैरह भेँ बार बार जाना पड़ता है उसके बजाय सब चीज बीज खाद वगैरह सब की सब चीजें उसके भकाम पर जाकर उसको दी जायँ और इस तरह उससे मेहमत करवाकर खेती की उपज को बढ़ाना चाहिए। मेरी विनती है सरकार से कि इस देश के जितने

पड़े लिये लोग हैं, जितने जानी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा बड़े खेती से दूर रहते हैं और बाहर जाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक प्यून जैसा घादमी भी डेढ़ सौ रुपये कमाता है। लेकिन खेती इतनी बड़ी चीज होती हुए भी, उस पर काफी लोग रहते हुए भी, हिन्दुस्तान के 47 करोड़ लोगों का जीवन होते हुए भी, उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी हालत है। इसलिए मेरी रिपोर्ट यह है कि उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय।

महाराष्ट्र के लिए 16 लाख टन धान या घनाज और 6 लाख टन बाकी सब दान वगैरह कम पड़ना था। लेकिन अब की हालत यह है कि 5.5 से 60 लाख टन तक कम पड़ने वाला है इसके ज्यादा से ज्यादा वहां दिक्कत है। इस देश में सब लोग साथ रहते हुए भी घनाज के घाब देखने से मानूस होता है कि यहाँ पंजाब में गेहूँ का भाव 40 से 50 रुपये क्विंटल तक है और महाराष्ट्र में 175 से 180 रुपये क्विंटल है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई दूसरा देश है या क्या है? पाकिस्तान बाजू और यहाँ की हद के अन्दर उसका रेट देखा जाय तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ एक देश के होने हुए भी इतना ज्यादा से ज्यादा फर्क है। इसलिए मेरी विनती है कि सरकार का बेसिकली, बुनियादी तिवार इस पर करना चाहिए। इसमें इतर उद्योग से पैरिय नहीं हो सकता। तीन या भाड़े नील हाथ कपड़ा है और पांच हाथ लम्बा कास्मी है तो जब नीचे कम पड़ता है तो ऊपर से खींचे और जब ऊपर कम पड़े तो नीचे से खींचे, इस तरह की पालिसी करने से यह काम नहीं चलेगा। नतीजा क्या होता है? सभी तक बहुत नुकसान नहीं हुआ है। जब मैंने घाड़ों से

देखा तो 20 लाख 50 हजार टन कम पड़ता है, हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और हम ने देखा कि इम्पोर्ट ज्यादा से ज्यादा 40 लाख या 60 लाख टन तक 63 और 64 साल में किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि 5 परसेंट इम्पोर्ट हम करते हैं। पांच परसेंट भी हम दस बारह बरों में अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सके तो हम ने क्या किया यह सवाल पैदा होता है। 88 मिलियन टन हमारे यहाँ पैदा होता है और कम पड़ता है 5 परसेंट। तो 17 बरों के अन्दर हमने इतने बड़े बड़े धन बड़े गये, सभी बातों में बढ़ाव हो गया लेकिन 5 परसेंट अनाज नहीं बढ़ा सकते तो यह पालिसी गवर्नमेंट की जो है वह बेसिकली काश्तकारों की नहीं है बल्कि माहाराजदारों की है, बकासत करने वालों की है या डाक्टर लोग या लहरी लोग जो है, जो कि ज्यादा बोलते हैं, लिखते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ज्यादा करती है लेकिन प्रामाणिक तौर से धानखेती जो गरीब हैं, जो सूखी रेंटी खाली भूमा में काम करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट का दुर्घट अतिकुल नहीं है। जो थोड़ा बहुत होनी है तो जो किज आप करके अनाज पैदा नहीं करते हैं, हम फिर उसके दरवाजे बंद करते हैं। यह पालिसी बिल्कुल बदलने की जरूरत है। जैसा पहले कहते थे, हमारे यहाँ अगली में एक तुर्गरी कहावत है कि "कजाने पंगारे न भणाने घ्यावे" यानी कजाने से खाना और मन मन से लेना, ऐसी कहावत थी। लेकिन अब जो कहावत है वह यह है कि भणाने पंगारे न कजाने घ्यावे, मन मन बीना तो कोई कजाने भिलता है। ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसी देश की हालात हो जाने के बाद और फिर अमेरिका से आने में हुआ भिलता पैदा होता है। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किन्तु काम पड़ता है, यह बाइडों में भी बताया है। 1962 साल में फेवर प्राइम ग्राप से 40 लाख 30 हजार टन खपत हुई है। 1963 साल में 50 लाख 10 हजार टन और 1964 साल में

[श्री तुलसीदास जाधव]

80 लाख टन तथा 1965 में 90 लाख 60 हजार टन, यह कंपर प्राइम ग्राप से लोगों के पास गया और प्रॉक्योरमेंट बिलना हुआ : 1960-61 में 5 लाख 50 हजार टन और 1964-65 में 30 लाख टन प्रॉक्योरमेंट किया। यानी 30 लाख 64 हजार टन का 1962 में इम्पोर्ट हुआ, 10 लाख 56 हजार टन 1963 में इम्पोर्ट हुआ, 60 लाख टन 1964 में और 60 लाख टन 1965 में इम्पोर्ट हुआ। 60 लाख टन मंगाया हुआ और 30 लाख टन प्रॉक्योर किया हुआ घनाइन इन दुकानों में बांटा गया। तीस लाख का प्रॉक्योरमेंट हुआ और खानी पचास या साठ लाख टन की कमी पड़ी है। मेरी प्रार्थना है कि हम को घन्य योजनाओं को छोड़ कर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि बरस दो बरस में प्रत्येक के मामले में घाटलिजिंग हो जाए। हमारे महाराष्ट्र को बांध मिनिस्टर ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि दो बरस में महाराष्ट्र स्वावलंबी हो जायेगा। ऐसी ही प्रतिज्ञा केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिए। कई वक्ताओं ने कहा जैसे श्री मालवीय जी ने कहा और हेनुमंतशा जी ने कहा कि यहां घाबरा करने से कोई लाभ नहीं होगा, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।

मेरा कहना है कि घाप देहात के यूनित कांफेड्रसी, यह देखो कि बहाने पिल्लो जमान है और उस जमान का बिलना मकदूर है, फिर प्लान करके घनाइन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करो। केशन यह कहने से कि इतना फटीलाइजर हो गया और इतना पानी हो गया इसलिए इतना उत्पादन हो जायेगा, कोई लाभ नहीं होगा। इन बातों से कोई फायदा नहीं हो सकता।

मेरी महाराष्ट्र के लिए सरकार से बात बात प्रार्थना है और बात कर के जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब हैं, जो कि काश्तकार के घर से घाये हैं और जो काश्तकार के जीवन के बारे में जानते हैं, उनसे प्रार्थना

है कि हमारे महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा प्रनाजों और प्रशिक उत्पादन करने के लिए प्रयत्न करें।

Mr. Chairman: I would request hon. Members to stick to ten minutes each, so that we shall be able to accommodate as many Members as possible. If hon. Members are going to encroach upon that time to be given to others, then our sitting for one hour more after 5.30 p.m. will have no meaning. So, I would request hon. Members again to co-operate with me, and if necessary, if the House so desires, we shall sit even later than that. But let hon. Members see that they stick to ten minutes strictly.

Shri. Lakshekantham: Every year, the Food and Agriculture Minister used to give a rosy picture on the agricultural front, but this year, the very fact that he has said that we cannot dispense with the imports and for the present we cannot think of suspending imports, shows the gravity of the situation on the food front.

Yesterday, the hon. Minister had explained that the States had co-operated with him fully, and yet, due to the failure of the monsoons and other bad conditions—it was not so much the failure on the agricultural front as such—the present situation has come about; the food situation today is more a God-made one than the result of folly or failure of the human elements.

My hon. friend Shri Jashvant Mehta was saying that the States did no co-operate. But I would like to say that the States were enthusiastic and rather over-enthusiastic in the matter. As far as my State of Andhra Pradesh is concerned, the procurement order was issued in October, 1965 itself, and efforts have been going on in that direction. But, recently, as I have already said, nature has been very cruel to us.

I had visited by constituency on the 15th of this month again to study the conditions in my district. I may submit that my district is the worst hit in the whole of Andhra Pradesh. Even the surplus States like Andhra Pradesh and Madhya Pradesh are talking as if they are going to be deficit States to the extent of many lakhs tons of rice and other millets. The report of the Andhra Pradesh Government says that in my district of Khammam even 10 per cent of last year's production of millets would not materialise. Nearly 17 districts out of 20 are in this condition. According to Government reports, there will be a deficit of 5½ lakhs tonnes in rice production during the kharif season, that is, there will be a production of 30 lakh tonnes as against 35.5 lakh tonnes last year. The fall in rice production during the rabi crop is also estimated to be 6 lakh tonnes. There has been no rain in the last week of September, in the whole October and November.

When I visited my constituency, it was a very painful sight to see the crops. In some places, the crops were not sown. Some were near tanks; but at the watering stage, the ryots are not able to water the crop at that crucial stage with the result that the plants are withering away. It has a most agonising sight to see.

The hon. Minister also mentioned about scarcity of fodder. We can at least talk about scarcity of food. But the dumb animals when they do not get fodder cannot even do that. How we are to meet this situation is also another problem before us.

Yesterday I was told in a friend's house that in Delhi the price of meat has come down very much because people from the villages are bringing these animals and selling them because they do not have fodder to feed them. When I visited by constituency last time, the Panchayat Minister of Andhra Pradesh was also there. He said that the Chittoor district in Rayalaseema was in the worst drought condition. He went to a panchayat

simiti to give them certain aid he could. There they give him Rs. 1 lakh for the defence fund. Another panchayat samiti gave him Rs. 80,000 for the defence fund. He asked them: 'How' is it that with this condition, you are giving Rs. 1 lakh and Rs. 80,000 for the defence fund? They replied, 'We will rather starve and die, but we will defend our freedom'. This is the spirit of the people.

For becoming really self-reliant, there has to be a three-pronged drive to achieve self-sufficiency. It should be based on more production, equitable distribution and a voluntary cut in consumption. This is the only way to preserve our self-respect in the international field.

The Minister has rightly asked for the co-operation of all political parties since we are facing two enemies on our borders, and at the same time there is this situation. I hope all political parties will surely give him that co-operation necessary in this respect.

In a way, this situation has engendered in us a mood of self-reliance in so far as our requirements on the defence front and on the food front are concerned. If some people outside are taking advantage of the situation in which we are placed externally and internally and if they think that they can mix politics with food and can apply political pressure, they must understand that Indian public opinion is very sensitive. All freedom loving democracies must realise that India alone can counter the Chinese menace and save democracy in South East Asia. They must realise that it is advantageous and essential from the point of view of the preservation of democracy in this region that Kashmir should be with India rather than with Pakistan. The wall of Ladakh, the bulwark of defence against China will disappear if Kashmir goes to Pakistan. So even if they had been thinking on these lines, they must now rethink about this matter.

[Shrimati LakshmiKanthamma]

After so much discussion and the determined stand taken by us, the US Ambassador has now made it clear that PL 480 will not be used to shape our political thinking. But still, may be sometimes as friends, they think we are depending too much on them and therefore we should concentrate more and more attention on our own agricultural production and increase it to become self-sufficient. That may also be one of their ideas. Still, this misunderstanding is there that since a long-term agreement is replaced by a short-term one, this kind of doubt is still left in the public mind in India. Even some of the leaders in the United States also feel that they should continue this pipeline of supplies of foodgrains and even to the extent of 10 million tons a year, but still, as the Minister yesterday has pointed out, there is uncertainty and we do not know when the pipeline will break. So, our aim should be more to rely on ourselves.

Mr. Chairman: Please conclude within one minute.

Shrimati LakshmiKanthamma: Already a national tempo has been created that we should prefer to starve rather than accept any national humiliation in anyway. Our jawans have vindicated our national honour at the front, we should not spoil the picture that has been created by suffering any humiliation at the hands of any other country.

Mr. Chairman: Ten minutes are over. Swamiji.

श्री रामानन्द जाम्श्री (जमशेहीनाट) :

सभापति महोदय, खाद्य समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर आपने मुझे दिया है, उस के लिए मैं आप को धन्यवाद करता हूँ।

माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के विचार सदन के सामने रखे हैं मैं इस

विषय में केवल समालोचना नहीं करूँगा बल्कि मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। सब से पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रथम पार्लिसी में मामूळ परिवर्तन नहीं किया जायेगा, तो खाद्य समस्या हल नहीं होगी।

हमारे देश में बहुत से फारखाने ऐसे हैं, जिन्होंने हजारों बीघा जमीन घेरी हुई है, जो कई सानों से बेकार पड़ी हुई है जब तक वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं होता है, तब तक के लिए उन जमीनों को जोतने वाले के लिए दे दिया जाए। उन्हीं जमीनों में हजारों मन गन्ना पैदा हो सकता है।

कई ऐसे फारखाने भी हैं, जिनके लिए सरकार ने जमीन एलाट की है, लेकिन वह जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है और उस में न तो कोई काम हो रहा है और न कोई पैदावार हो रही है, जब कि वह अच्छी उपजाऊ जमीन है। ऐसी जमीनों को भी खेती के काम में लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार रेलवे की भी हजारों बीघे जमीन पड़ी हुई है। वह जमीन फ़ासक़ारों को जोतने के लिए इस शर्त पर दे दी जाए कि जब आवश्यकता होगी उनको ले लिया जायेगा। बड़े बड़े क़ाश्कारों के पास भी हजारों बीघे जमीन है, जो बंजर पड़ी हुई है जो गरीब मजदूर काम करने वाले हैं, जो अन्न पैदा करने में सक्षम हैं वे भेड़-बूढ़ी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसी जमीनें नहीं दी जाती हैं और वे बेकार पड़ी हुई हैं जब तक सरकार इस प्रकार की पार्लिसी में परिवर्तन नहीं करेगी, तब तक केवल लेम्बर देने से काम नहीं चलेगा।

सरकार जो रुपया देती है, उस की वितरण-ध्वंस्या में भी कड़ी गलतियाँ हैं। मैं ज्यादातर देहात में धापा करता हूँ। मुझे अनुभव है कि सरकार के द्वारा ज़ाकीं में किसानों को बीज के लिए या दूसरे खर्च में जितना रुपया दिया जाता है, उस का

दुरुपयोग होता है। आधी रकम तो सरकारी कर्मचारियों की जेब में चली जाती है। अगर किसी गरीब किसान को गड़्ढा खोदने के लिए दस रुपये मिलते हैं, तो उस में से पांच रुपये तो बी० डी० ओ० या ब्लाक के किसी सरकारी कर्मचारी की जेब में चले जाते हैं और बाकी पांच रुपये किसान वैसे खा जाता है। तो पांच रुपये में गड़्ढा कैसे खोदा जाये और कम्पोस्ट खाद कैसे बने।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि वह एक विधेयक लाये, या वर्तमान कानून में संशोधन करे कि कोई भी किसान बिना पक्का गड़्ढा बनाए कम्पोस्ट खाद न रखे और सरकार की तरफ से इसके लिए किसानों को पैसा दिया जाये।

चूँकि मैं खाद्य समस्या पर बोल रहा हूँ, इसलिये मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से नहीं कहूँगा। मुझे दो चार सुझाव देने हैं। एक कानून बनाया जाये, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए बाध्य किया जाये। आज पशुओं के रखने की ठीक व्यवस्था नहीं है, इसलिये उनके पेशाब और गोबर को जला दिया जाता है। अगर गांव-गांव में गोबर-गैस प्लांट लगा दिया जाये, तो उससे कम्पोस्ट खाद भी मिल जायेगी और लोगों को खाना पकाने के लिये ईंधन भी मिल जायेगा। कम्पोस्ट खाद के गड़्ढों के लिए सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है, वह पड़ा रहता है। चूँकि रिश्वत दिये बिना किसानों को वह पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए वह लेप्त हो जाता है।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है, को-ऑपरेटिव सोसाइटियों के सुपरवाइजर वहुत से फ़र्जी नाम भर लेते हैं और उस खाद को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। सरकारी कर्मचारी भी एजेंट से मिल जाते हैं और यह दिखला देते हैं कि खाद बांट दिया गया है वह खाद ब्लैक मार्केट में बिकता है। गवर्नमेंट

के द्वारा खाद का जो दाम निश्चित किया गया है, किसान को उस पर खाद नहीं मिलता है। यद्यपि मैं खेती नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भी चालीस एकड़ का कास्तकार हूँ। मुझे अनुभव है कि हमें खाद नहीं मिला, लेकिन दूसरों को दे दिया गया। पूछने पर मालूम हुआ कि उन्होंने ब्लैक में खरीदा है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ब्लाकों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और सरकार इस बात को जानती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता है। आज स्थिति यह है कि राज ब्लाकों में विलेज वर्कर और ग्राम सेवक आदि अफसर बन कर जाते हैं लेकिन लोगों की कोई सहायता नहीं करते हैं और न ही उनको कुछ सिखाते हैं। मैं ने एक विलेज वर्कर को अपने मकान में साल भर मुफ्त रखा हुआ था। उस की हरकतों को देख कर मैं ने कहा कि तुम सब गड़बड़ करते हो, जब तुम स्वयं गोबर को लाकर जलाते हो, तो तुम प्रचार क्या करोगे। जब मैं ने उसको अपने यहां से हटने के लिए कहा, तो उसने मेरी शिकायत कर दी। मेरे यहां ट्यूबवैल बना हुआ है और मैं उससे सिंचाई करता हूँ, लेकिन उस ने यह शिकायत कर दी कि स्वामी जी ने कोई कुआं नहीं बनाया है, इस लिये सब रुपया एक ही बार सूद के साथ इनसे वसूल कर लिया जाये मैं ने इस बारे में कलेक्टर को लिखा। उन्होंने जब देखा कि सचमुच कुआं बना हुआ है, तो उस विलेज वर्कर को हटा दिया गया। वह सरकारी कर्मचारियों का हाल है।

ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन को सरकार कोई दण्ड नहीं देती है। दुनिया में जो काम नहीं होता है, वह रिश्वत से हो जाता है और जो रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, वह फिर रिश्वत से छूट जाता है। हमारे नन्दा जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतना आन्दोलन किया, लेकिन मेरी निगाह में भ्रष्टाचार घटा नहीं है, बल्कि बढ़ गया है।

[श्री रामानन्द शास्त्री]

दुपका कारण हम ही लोग हैं—मिनिस्टर है, नरकासो धकपगान है और हम भी हैं, मैं इन बात को मानना हूँ। हम सब प्रोव्हाबार के बारे में बिश्वासि हैं, लेकिन वास्तव में दिये गये धन-पत्रेरा हीतर है। हमारे डिपुटी ग्राय मिनिस्टर के पास मेरा काम है। धगर में उनके बारे में कहूँ, तो दूसरी चीज पैदा हो जायेगी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ। प्रोव्हाबार भी हमारे धगर से चल रहा है। जब तक हम उसको यहाँ से नहीं मिटावेंगे, तब तक प्रोव्हाबार दूर नहीं होगा।

18 hrs.

सरकार दूसरी बात के लिए कहाँ-हाँ जाया दे रही है। धगर वह किसानों को पतिशाय का से कम्पासि खाद के लिए गहड़ा खाने के लिए कच्चे और इन प्रकार ज्यादा से ज्यादा कम्पोस्ट खाद की व्यवस्था की जाये, या ग्राय मंत्रः का हल करने में सहायता मिल सकती है। किसानों के मनुष्यों को बावने के लिए मोर्पेट के पक्के फर्म बनाए जाएँ, ताकि उनके पैसाब और मोटर खादि को रकड़ा कच्चे गहड़े में खाद को व्यवस्था की जा सके। सरकार ये ज्यादा किस लिए है? क्या ये ज्यादा विश्वासिता के केन्द्र बनने के लिए है? मैं ने हरिद्वार के पक्ष एक बाँ ० ० ० ० का देखा है, जो राजाना मंत्री को लेकर हर की पीड़ी पर पहुँच जाते हैं। जब दिवाया गया तब बना बना। उन को काम कुछ है नहीं। एक तरह की तपाम थीजें हो रही हैं और इन सारी की सारी चीजों के लिये गान्धी हमें खानी पड़ती है या सरकार को खानी पड़ती है। लेकिन सरकार के कामये हम साते हैं तो वह भी कुछ कारंखार्ड नहीं करती। जिस धावमी की हम शिकायत करते हैं उसी के मानने सारे कामजात में ज्यादा गन दिये जाते हैं। यह नहीं कि किसी दूसरे धावमी से एकबायरी करई जाये और न्यायि दिया जाये। धगर नीचे

बाने लोगों के कहने के अनुसार मात्र काम करना है जो पाँटे गीँडे धकभरों को हजाउं हाये तनकवाह देकर क्यों देल के ऊपर धार काम रहे हैं। जिस धादपी के प्रोव्हाबार की शिकायत हम करते हैं उसी के पास सारे कामज पत्रुंज जाते हैं। इस तरह से धाय कौसे काम कर सकेंगे। इस लिये मैं धाय से कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े फार्म पटिमक को दिये जाये और पत्तिनका को सरकार हर प्रकार की ज्यादा से ज्यादा सहायता दे। सभी धाय गहला पैदा कर सकते हैं। धाज जो गाँव के मजदूर हैं जो खेत में हम बनाते हैं उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है और फकील, डाक्टर, और सड़खें के रहने वाले लोगों के बड़े-बड़े दस-दस एकड़, पाँच एकड़ के फार्म बड़े हुए हैं जो कि इनके के नीचे बैठते हैं। मजदूरों को प्राय चरपेट खाना नहीं मिलता तो वह कैसे खेत में काम करेंगे। धगर बड़े-बड़े फार्म छोटे-छोटे बाशनकारों को दिये जाये और कामकारों को मदद की जाये जो वह धायका काम पूरा कर सकते हैं लेकिन जो धादूर है जब उनका धर पेट रोटी नहीं मिलती है तो वे उन्हें काम करते हैं और दुनिया धर में हमें बदनय करते हैं और कहते हैं कि उनको खाना नहीं मिलता। इस वकत महंगाई इतनी है कि जिसका ठिकाना नहीं है। मैं धामता हूँ कि इस समय भी मजदूरों को छः घाने रोज मिलते हैं। धना उन छः घानों में क्लू पाँच धादपियों का पत्तिन कौसे कर सकेगा। हम को विचार करना पड़ेगा कि जो लोग खाना कम देते हैं वे सब प्रोव्हाबार के बाँधी हैं।

इन सबों के साथ मैं धनुरांय करणा कि जो बातें मैं ने बतलाई हैं उनके ऊपर धनी महोदय गौर कने क्योंकि यह देल के उत्थान में सहायक होगा।

श्री कान्हेय विठ्ठु मिश्रजी (मजदूर) :
समापति महोदय, मेरा समय समाप्त होने से दो मिनट पहले मुझे बताना दीजियेगा।

इस समय गन्धु के ऊपर जो धान का संकट है उसके लिये मैं दलान घाटें प प्रत्यारोप विधि का ही आश्रय लेता हूँ। मैं छोटे-छोटे मुसाव दूना घाटें से मुसाव है दो प्रकार के। एक तो जो धान करने के है त्रिन से दुमिल का रोख र हुं जोधगा घाटें हमें विदेकां से धान नहीं पाना पड़ेगा। दूसरे कुछ घाटें के लिये हैं।

पहले हमें यह काम करना चाहिये कि चावल पर जो पाणिश की जाती है, जो चावल का बाहर का भाग उतारा जाता है, वह बन्द कर दिया जाये। इससे चावल में जो तरब होता है उसका 10 प्रतिशत नाश हो जाता है। इस तरह से गेहूँ और दालों के ऊपर जो विस्का-बंकर होता है उसको भी नहीं हटाना चाहिये। गेहूँ बस्की में रोसा आये, धान बाण ही लेकिन उस बंकर को न हटाया जाये। उसमें विन्डमिन घाटि के तत्व प्रतिक होते हैं इस लिये उन के साथ ही धान खाया जाये। इस तरह से 10 या 15 प्रतिशत धान बचेगा।

एक मासगीर सहाय्य : चावल का तुष भी ले लिया जाये।

बी जाबेह सिंह सिद्धांती : उसी भी ले लो। वहाँ बरताने ही। इसी तरह से दालों की चूरी है। दाल को घ घी मत्त, त्रि वका मत्त उतारें। दूरी के साथ हम इन चीजों को बेरी उतार कर जैसे धानू, धकर-काद, गाबर, इतै: मधियां, कच पून, केले घाटि इन, बी कि केन में बरही उपजते है और पत्र तो बचा में सहाया पदुवारों। मुझे विश्वास है कि पत्रान की दया से अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम धान का संकट दूर कर सकेंगे।

घाटनी खोज यह है कि मागीं घोर पछनी पर बहुत बल मत्त हो। बर्निक तावाओं में निरादे डान दी। वे कन्वे बी जाये जायेंगे,

पन्वे: भी जाये जायेंगे, मिठाई भी बन जायेगी और घाटा भी बनेगा। सब जोड़े दस से हो सकती है।

एक और चीज है खोपा जिस को मोना या कोकोनट कहते हैं उस में से तेल या बी जो बाहें निकाल ले, लेकिन बाकी जो चीज रह जाती है उसके साथ डिस्ट्रुट बनवा लें। इस तरह से वह भी धान का काम लेंगे। यह हमारे विस्तृत विचारों का मुसाव है।

घब में घाप से निवेदन कर्क कि घाप किसानों को मुबिधा दीजिये, जिससे वह बीड़ा और धाने चल सकें। इस से हमारा धान का संकट दूर हो जायेगा और हमें बाहर से धान नहीं मंगाना पड़ेगा। जो घाप की महूर और नथिया हैं उनके फिनारे पर घाप जगह जगह पर झीतें बनायें ताकि जो बाड़ का पानी घाये वह इन झीतों में छके। इसी तरह से नहरों के पास जो बर्षा का पानी ज्यादा प्यता है वह जो बकेगा अगर उनके पास धाप बड़े बड़े तालाब और झीतें बना दें। तो इस पानी को हम विचारों के काम में ला सकते हैं।

घाप ट्यूबवैत लगायें लेकिन साच से बेसी कुएं भी बनायें। ट्यूबवैत वहाँ भी लगायें जहाँ पर बाबरही, पानी ज्यादा हो जाता हो कम घाटा हो। वहाँ से घाप उसे निकाल कर बाहर बेयें जिस से बाहर में कमी घायेगी और वहाँ बेतो घच्छी होती रहेगी।

इसी तरह से जो किसान हैं उन को घाप घेरना दीजिये। मान बीखिये कितने के पास पचास बीघे अधीन है तो उस पचास बीघे जमीन में पांच बीघे अधीन वह छोड़ दे और वहाँ लकड़ी पैदा की जाये। लकड़ी उब में छी, घास हो और उब के बीघे के जोड़ बना दिया जाये, कच्चा ही लही, ताकि बरसात का पानी भी उस में बके। इस से सच्ची बाब घाटि होने के सम्बन्ध में घाप बाब उठा सकते हैं।

[श्री जयदेव सिंह सिद्धांती]

बाँधी बाल यह है कि गुड़ पर जोर दिया जाये, बाँधी पर नहीं। क्योंकि गुड़ में एक फायदा है। उसे दूध के साथ भी खाया जा सकता है और छाछ के साथ खाया जा सकता है। जो मजदूर कोरूह बगीरह में काम करते हैं, उन को जा कर प्राप देखिये, वह रस भी पाते रहते हैं और छाछ ला कर उसके साथ भी कास में लाते हैं। छाछ गांव में भोल तो भिखता नहीं है इसलिए उन मजदूरों को मिल जाता है। गुड़ पकता रहता है उस को खा कर वह एक-एक दाँदों समय घन खाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। इसलिये सरकार को गुड़ पर ज्यादा जोर देना चाहिये।

हमारे यहां बाँधी बनती है तो उसके सम्बन्ध में एक बात की याद दिला देना चाहता हूँ। ग्रामी में जिला मेरठ में गया था। वहाँ वो मिलें है। जो बाँधी का हिस्सा है वहाँ से एक मिल नजदीक पड़ती है, लेकिन उस में गन्ने को जाने नहीं दिया जाता। जो मिल दूर पड़ती है वहाँ किसानों को मजदूर किया जाता है कि वहाँ घनना गन्ना भेजें क्योंकि जिन का इंटरैस्ट है वे लोग सरकारी लोगों से मिले हुए हैं। सरकार को इसकी जांच करती चाहिए और ऐसी सुविधा देनी चाहिये कि किसानों के नजदीक जो मिल हो उस में वह गन्ना ले जायें।

जा.स.त.वा. हवि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० दा० ज.सिद्धांती) : मिलाँ का नाम बतासाइये।

श्री जयदेव सिंह सिद्धांती : नाम बता देता हूँ। एक बीराला है और एक बागपत। मेरठ जिले में ये दोनों मिलें हैं। जिलाली गांव वाले बीराला मिल को भेजें इस की मंजूरी भी दे दी गई लेकिन लोग केन कमिश्नर के पास पहुंचते हैं या मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं, और वे लोग बजबूत करते हैं कि नहीं

तुम बागपत ले जाओ, यद्यपि बागपत दूर पड़ता है। इससे किसानों का हर्ज होता है। मैं गांव का नाम भी बतला रहा हूँ कि जिलाली है और मेरठ जिले में दोनों मिलें हैं। मैं ने दोनों का नाम ले दिया है।

मिलाँ के साथ में एक बीज किसानों के लिए और बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ट्रेक्टर बगीरह रखते हैं और साथ में ट्राली भी रखते हैं। ट्राली में गन्ना भी ले जाते हैं और मिल में पहुंचते हैं। जिन समय खेत में खाद भेजनी होती है उस समय उस को भी उसमें ले जाते हैं, मंडी में घनाज और गुड़ ले जाते हैं तो भी ट्राली में भर कर ले जाते हैं। इस से खाद्य मंत्रो का काम तो ठीक होता है क्योंकि उन्हें सुविधा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वाले उन पर टैक्स लगा रहे हैं। इस से खेत तंग और मजदूर हो जाते हैं। मैं ने एक गाड़ी का सब्य देखा। एक घाना है उसके बाहर उसकी रोबो गन्ना और कहा गया कि इस का टैक्स दो। घनर नहीं देते तो घनतत में ले जा कर उन पर जुर्माना किया जाता है। इसलिये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को यह कहना चाहिये कि खेतों के काम में जो ट्राली लाई जाये उस पर टैक्स न लिया जाये।

तम्बाकू बगीरह के जो खेत है उनको कुछ समय के लिये तो बन्द कर ही दिया जाये। यह काम मैं जहरी समझता हूँ। जहर बोयें और घनाज न बोयें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

सड़कों के ऊपर और नहर की पटरियों पर कुछ फसदार पेड़ लगाये जायें, जैसे आम है, जामुन है। यह पेड़ लकड़ी भी देते हैं और फल भी देते हैं। इस तरह के पेड़ लगाने से राष्ट्र की घनाज की समस्या भी हम होगी और लकड़ी भी बराबर मिलती रहेगी। इसी के साथ किसानों के पास गोबर भी है। उस में से पांच बीघे छोड़ें जिस में जो रंगर है गाय बगीरह वह भी चली रहे।

इस से हमें गायाँ से भी दूध मिलेगा घीर जितना भी दूध खाया जायेगा उतना धन्न कम लगेगा घीर उसी बचत होगी घीर पॉण्टिक पदार्थ भी मिलेंगे । घीर गी घ्रादि की रक्षा भी होगी जिनके ऊपर कि हमारा राष्ट्र निर्भर है । गी के ऊपर हमारी सारी खेती निर्भर होती है ।

इसी तरह जैसे कि सरसों वगैरह की खली है, इसको बाहर भेजने से घाप को 25 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं । लेकिन घगर यह न भेजी जाय घीर खेतों में डाल दी जाय तो एक धरब रुपये का धन्न ज्यादा पैदा होगा । इसलिए खनी बाहर भेजना बन्द कर दें । घीर बिजली का, जो रक्षा के काम है या खेती के काम है उनमें बिजली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए । ट्यूबवेल में मीने देखा, ट्यूबवेल घ्रापरेटर एक घंटा ट्यूबवेल चलाने के लिए दो रुपये रिश्चत मांगते हैं घीर एक घीर खराबी है, जो ट्यूबवेल चार साल पहले बना हुआ था, जब सरकार से कहा जाता है कि घीर ट्यूबवेल लगाओ तो वह बोर्ड हटाकर के नया बोर्ड लगा देते हैं घीर कह देते हैं कि हम ने नया बनाया । मैं खुद चलकर के दिखा सकता हूँ । जो बिजली के घीर नहर के कर्मचारी है उनको कम से कम किसानों का हितवी होना चाहिए, वह समझें कि कब पानी चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए । लेकिन वह बेचारे ऐसे भेजे जाते हैं कि सात पीढ़ी तक जिनके यहां खेती न हुई हो, उनको लाकर वहां बैठा देते हैं । छोटी छोटी भूमि का बटवारा बन्द कर दीजिये घीर एक हद्द मुकरर कर दीजिये । गाँवों में प्रचार का जो घ्रापण साधन है, ध्रुवो का तो कोई जानता ही नहीं घीर हिन्दी में भी जो जाता है तो उससे भी बड़ी मुश्किल होती है । तो घाप डी० सी० को कहिये कि वह हर गाँव में खेती के जो साधन हैं उनकी मुनाबी करवावे कि किसानो मुन्हारा इसमें फायदा है । इससे तात्कालिक भी लाभ होगा घीर घामे के लिए भी लाभ होगा ।

श्री प्र० प्र० शर्मा : सभापति जी, प्राज देश के सामने दो बड़ी समस्यायें हैं । एक देश की सुरक्षा की तैयारी करना घीर दूसरे देश के घन्दर घ्राधिक से घ्राधिक धन्न पैदा करना । जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है सभी लोग इसके लिए एक राय होकर तैयारी कर रहे हैं घीर लोगों ने इसका परिचय भी दिया है जब पिछले दिनों में पाकिस्तान ने देश के ऊपर घ्राक्रमण किया । लेकिन देश की सुरक्षा के काम में सफल होने के लिए भी यह जरूरी है कि देश के घन्दर जो धन्न उत्पादन का काम है उसमें हम घ्राधिक से घ्राधिक सफल हो सकें । मैं यह कहना चाहता हूँ कि घ्राज तक सरकार के काम करने का जो तरीका रहा है, सरकार को जो घ्राघ नीति है खास तौर से धन्न उत्पादन करने की जो नीति है घगर यह पुरानी नीति कायम रही तो जैसा हमारे भाई काश्मीर के श्री मल्होत्रा ने कल ठीक ही कहा कि 1971 तक भी हम सेल्फ सफिशियंट यानी घपने देश के घन्दर जो धन्न उत्पादन किया जायगा उसके ऊपर घपने को निर्भर कर सकें, यह घ्राशा कभी पूरी होने वाली नहीं है । मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि 1971 तक ही नहीं बल्कि उससे दो चार पाँच बयं घामे का समय भी घगर कहा जाय तो उसमें भी कोई घत्पुन्ति नहीं होगी ।

मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि घ्राधिक से घ्राधिक धन्न उपजाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वह है सिंचाई का प्रबन्ध, सिंचाई की व्यवस्था । लेकिन देश के घन्दर करोड़ों एकड़ जमीन सूखी पड़ी हुई है । खास तौर से गंगा के किनारे जिसकी गैजेटिक बैली कहते हैं जहां पर बोड़ी सी सिंचाई की व्यवस्था होने से बर्ता पर दुगुना धन्न पैदा हो सकता है । सरकार यह कहती है कि कुछ राज्य हमारे देश के घन्दर ऐसे हैं जहां पर घ्राधिक धन्न उत्पन्न होता है जिसको सरप्लस स्टेट कहते हैं घीर कुछ ऐंग राज्य हैं जहां धन्न उत्पादन की कमी है, उसको

[श्री घ० प्र० मंत्री]

डेफिसिट स्टेट कहते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि यह सरप्लस और डेफिसिट स्टेट कैसे बने, क्यों बने? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? सिवाय प्रथम पंचवर्षीय योजना के हम ने सिवाई के लिए कौन से काम किये हैं जिससे कि देश के घन्दर प्रधिक से अधिक धन्न का उत्पादन हो सके। पिछले दस वर्षों में हम ने बराबर जोर एक ही बात पर दिया और वह दिया देश के औद्योगिकरण पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन आज जो धन्न की कमी इतनी बड़ी विकट समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि अगर पिछली दो योजनाओं में डिसीमल और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना की तरह अगर धन्न उत्पादन करने के ऊपर जोर दिया गया होता तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ, कि सरकार सिवाई की सुविधा देने का जो सुवान है उसकी नीति में परिवर्तन करे और खास तौर से उन मूबों के घन्दर जो कि डेफिसिट स्टेट कह जाते हैं वहाँ पर अधिक से अधिक सिवाई की व्यवस्था करे। इस सम्बन्ध में खास तौर से मैं अपने मूबों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उनको सदन के टेबल पर रखना चाहूँगा। इनको देखने से आश्चर्य होगा कि यू० पी० जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके बाद बिहार है या और दूसरे राज्य हैं। यू० पी० में करीब करीब 11 हजार ट्यूबवेल लग गये हैं और इसी तरह से बिहार में 5 हजार लगाये गये हैं। लेकिन अगर मंडास को देखें तो वहाँ पर 1 लाख 35 हजार ट्यूबवेल लगाये गये हैं। तो अब ये (यू० पी० और बिहार) स्टेट डेफिसिट नहीं होने तो क्या होने। जहाँ पर सिवाई की ऐसी सुविधा है, वहाँ पर अधिक धन्न कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ सम्भावित बहुोदय कि दो वर्षों हो गये, दो वर्षों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र (बक्सर संसदीय क्षेत्र) में

जो गंगा के किनारे की बड़ी उपजाऊ भूमि है मैंने सर्वे कराकर दिया है, प्रधान मंत्री को भी लिखा है और खाद्य मंत्री को भी लिखा है, कांग्रेस की कार्यकारणी समिति में भी लिखा है, और मैंने एक चैजेंज दिया है कि उस 1 लाख 35 हजार एकड़ जमीन में वहाँ पर कोई सिवाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अगर सिवाई की व्यवस्था कर दी जाय, दो सौ ट्यूबवेल लग जायें जिनकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये होगी तो वहाँ पर 35 से 40 हजार टन तक अधिक धन्न का उत्पादन हो सकता है। मेरे मूबों के घन्दर आज जो धन्न की कमी है, वह 11 से 13 लाख टन सामान्य है जो बिहार की राज्य सरकार केन्द्र से देने की मांग करती है और केन्द्रीय सरकार प्रति मास 35 से 40 हजार टन से अधिक बिहार सरकार को धन्न नहीं दे पत्ती है। तो इस तरह से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर उस क्षेत्र को धावाट किया जाय, वहाँ पर सिवाई की व्यवस्था की जाय तो 35 से 40 हजार टन अधिक धन्न एक फसल में, दो फसल में नहीं, पैदा हो सकता है जो कि बिहार सरकार के एक महीने के डेफिसिट को पूरा कर सकता है। इस तरह से जहाँ जहाँ भी सिवाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ सिवाई की व्यवस्था करनी चाहिए।

खाद्य मंत्री की जो यह पत्रिका निकली है इन्फोर्मेशन फूड प्रोडक्शन इन दिव्स कन्ट्री, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। उनके कहने के मुताबिक खाद या फर्टिलाइजर यह अधिक से अधिक लोगों को देना चाहते हैं। उसका नवीज क्या होगा? फर्टिलाइजर उसी जगह में उपयोगी हों सकेगा जहाँ सिवाई की व्यवस्था है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर को जरूरत नहीं है, किसानों को कोई भी ऐसी पौध देने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग गाँवों में जाते हैं तो किसान की एक ही मांग होती है कि हमारी सूखी

जमीन में तुम पानी दो, हम जानते हैं कि हम कंसे धधिक बनाज पैदा कर सकते हैं । इर किसान इस बात को जानता है । प्रधान मंत्री ने देश को धारवासन दिया इस सदन के जरिये से कि जहां तक डेती का काम है उसमें रुपये की कमी नहीं होगी । तो मैं श्राङ्गा कि श्राछ मंत्री और सरकार, धाय भी जो धन्न उत्पादन करने की उनकी नीति है उस में परिवर्तन करने धौर सब से पहले सारा काम बन्द करके जहां जहां पानी की ध्यवस्था नहीं है, किसानों को पानी दें धौर इस देश का किसान धन्न उत्पादन करेगा, तभी जो धन्न का धभाव है वह पूरा हो सकता है ।

मैं वितरण धौरहू के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । वितरण के धन्दर जो गरेषानो धौर दिक्कत होनी है वह इस नियो होते हैं कि धन्न का धभाव है । जिस बांज की कमी होरी है उरी के वितरण का भी सवाल पैदा होता है । धगर बांज धधिक से धधिक पैदा हो तो वितरण का सवाल हमारे सामने नहीं भा सकता । इसलिए मैं बड़े धट्ट के माध धपने ध्राध मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हू कि जिस बात का मैंने जिक किया है उस पर ध्यान दें धौर धगर बाहें तो उसको धल कर देखें ।

एक बात धौर धन्न में कठना चाहता हू कि हमारे देश में जो तबु सिर्चार्ड योजना है वह तो कृषि मंत्रासय के धघोन है । मैं ट्यूब वेल इत्याधि, जिनको माइनर इर्रीगेशन भी कहते हैं । धौर बाकी जों सिर्चार्ड का काय है वह सिर्चार्ड विभाग के धघोन है । नवीजा यह होता है कि कृषि विभाग को तरफ से धगर ट्यूबवेल लगाया जाता है तां उस ट्यूबवेल में बिजली का कनेक्शन पावर धौर इर्रीगेशन विभाग डारा देर में लगाया जाता है क्योंकि बिजली उनके धघीन है । इसका नवीजा यह होता है कि जो ट्यूबवेल लग जाने हैं उन में से बहुत से बिजली न पिपन के कारण बंकार पड़े रहते हैं । इसलिए

धाखिर मैं मेरा यही यही सुझाव है कि जो भी सिर्चार्ड का काम है उसको एक ही मंत्रालय के धघोन कर दिया जाए, माइनर इर्रीगेशन को भी धगर ऐसा नहीं होता है तो कृषि मंत्रालय माइनर इर्रीगेशन के काम को सब से पहले ले, इसके बाद कर्टिलाइजर धादि को बात करे ।

मैं धापको धन्यवाद देता हू कि धापने मुझे धोका दिया । धाय बा यह धोका मैं धपने लिए नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं इस बात को साहित करना चाहता था कि पार्लियामेंट के सदस्य खास नीध से कांसेस पार्टी के सदस्य देश की हालत से इतने ज्यादा चिन्तित हैं कि धधिक समय में बैठ कर भी सरकार को सुझाव देने को तैयार है । देश की खाछ समस्या मुरुधा समस्या के धार सब से महत्वपूर्ण समस्या है धौर इस कारण इसका समाधान होना चाहिये ।

Mr. Chairman: I think I can accommodate only one or two more within the time extended by the House. If it is the desire of the House to sit some time more, I am prepared. What is the desire of the House?

बी धुरम धण्य कधधाय : धगर इस समय को उसमें न जोड़ा जाए तो हम सात बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं ।

Mr. Chairman: So we sit for some time more. We sit upto 7.00 P.M.

बी धण्यधोर इत्ताय सिंह (उपरा) : समापित मधोदय, मैं धापको धन्यवाद देता हू कि धापने मुझे बोधने का धयधर दिया । मुझे धय था कि कहीं ऐसा न हो कि माध धी मुझे बिना जाले बना जाता रहे ।

कल मैं माननीय ध्राध मंत्री महोदय का धाधय बड़े ध्यान में सुनना रहा । । जब कमी ध्राध स्थिति पर यहां बहस प्रारंभ होती है तो मैं ध्राध मंत्री महोदय का धाधय बड़े ध्यान में सुनता हू । लेकिन हर धार में इस धार मैंने उनके धाधय में धन्नर देखा । धभी तक बिहार को वह एक डेफिडिट स्टेट

[श्री राम जेठर प्रसाद सिंह]

बताते थे और इस वक्त जब कि सारे देश में और इस सदन के अंदर लोगों से यह आवाज आ रही है कि यह स्थिति संकट की है, और सारे देश में अकाल की परिस्थिति हो गई है, उस समय उन्होंने ऐसा एलान किया कि बिहार में खाद्य की स्थिति संतोषजनक है। इस एलान से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिये कि जिस प्रकार उन्होंने आज पिछले दो वर्षों में अन्न की कमी के समय बिहार में ठीक समय पर अन्न नहीं पहुंचाया, और जो अन्न उसको देने का कमिटेन्ट किया था उसको भी नहीं पहुंचाया, उस पृष्ठ भूमि में मुझे सन्देह ही रहा है कि क्या सारे बिहार को अच्छा खाने का उन के मन में इच्छा है। इसलिये मैं उनके आश्चर्य को सन्देह की निगाह से देखता हूँ और आपके मार्कत प्रधान मंत्री महोदय से अपना यह सन्देह जाहिर करना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि वह ऐसा न समझे कि बिहार में खाद्य की स्थिति अच्छी है। बिहार को भी स्थिति वैसी ही है जैसी कि सारे देश को है। यह बात सच है कि मर्कट के वक्त में उत्तर बिहार में मर्कट जरूर हुई थी।

मैं आपसे निहायत घटब से कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के सभी राज्य हिन्दुस्तान के बराबर के भागी हैं और एक प्रदेश में अन्न कोई चीज पैदा होती है तो उस चीज का उपभोग करने का दूसरे प्रदेश को भी बराबर अधिकार है। लेकिन खाद्य मंत्री महोदय ने पहले जोनल सिस्टम बनाया और देश में एक जगह से दूसरी जगह अनाज ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इससे राष्ट्रीयता की भावना पर कुठाराघात होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी प्रदेश में कान्यसा पैदा होता है, तोहा पैदा होता है, पबरक पैदा होता है, सोयेत पैदा होता है या और ऐसी चीजें पैदा होती हैं तो उनके दूसरे राज्यों में पहुंचा कर उसी दाम पर उनका उपभोग करने का अधिकार अन्न

बागों को भी दिया जाता है। लेकिन उन राज्यों में जिन में ये चीजें दूसरे राज्यों को भेजी जाती हैं, अन्न न भेजना राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है। ऐसा होने से उस राज्य के लोगों के क्लेशों में यह भावना पैदा होती है कि हमारे साथ भारत सरकार अन्याय कर रही है, हमारी चीज को तो ले जाती है पर हमको अन्न नहीं पहुंचा रही है। आज जब कि सारे देश की परिस्थिति एक समान हो गयी है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सर्व-बुद्धि ज्ञान्त्री चाहिए और जोनल सिस्टम को तोड़ देना चाहिए।

मैं आपसे निहायत घटब के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री महोदय ने एलान किया है "जय जवान" "जय किसान"। मैं इस स्लोगन को कोई दो बात नहीं समझता, क्योंकि जो आदमी किसानों करते हैं वही आदमी जवान बन कर युद्ध मोर्चे पर जाते हैं। आप मानेंगे कि देश में आज 80 प्रतिशत लोग किसानों करते हैं और ज्यादातर इन्हीं के ऊंचे भाज खाने बन कर खून देकर देश को रखा करते हैं। खून देने वाले खून दे कर रखा करते हैं और उनके माता-पिता घर में रह कर किसानी करते हैं और देश को अन्न देते हैं जो कि आपको और हमको खाने का मितता है।

आपने पहले बड़े शहरों में अन्न देने की बात कही है। जो आपका सरकूलर गया है देहातों में हमने उसको देखा है। उस में ऐसा है कि जिस आदमी के पास पांच या पांच एकड़ से अधिक भूमि हो उसको अन्न नहीं मिलेगा। यह किसानों अन्यायपूर्ण बात है कि जो अन्न पैदा करते हैं उन्हीं को अन्न नहीं दिया जायेगा। अगर किसी कारण उस आदमी के पास अन्न नहीं रहे तो उसे आप अन्न नहीं देंगे जब उससे ले कर अन्न के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि वे शहर में रहते हैं और अन्न बालों की जो इन्जिनसिपल एरिया के बाहर अभीन है उसको पैदा बंध कर वे पैसा कमाते हैं। मैं निहायत

घरब के साथ घपने मंत्री महोदय के पास देहात के बरीबों का संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि श्री गरीब किसान हैं उनके साथ भी उचित व्यवहार कीजिए। घाप घन देना चाहते हैं तो सब को दोजिए, और अगर घापके पास घन की प्रचुरता नहीं है तो छोड़ दीजिए सारे लोग घपना इतनाम कर लेंगे। जो घन घाप देते भी हैं वह उनको पूरा नहीं देते हैं।

बसूतों की जो नीति घापने भपनायी है वह भी न्यायपूर्ण नहीं है। अभी हमारे दोस्त सरबू पांडेय ने सदन में कहा, बिहार को स्थिति बताते हुए, कि वहां कहा गया है कि तीन एकड़ से ज्यादा जिन लोगों के पास जमीन है उनके यहां पैदा हो या न हो उनके धान देना हीना। जिस व्यक्ति के पास धान नहीं भी है उसको भी धान देना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं को ऊपर के लोग बनाते हैं और वे नीचे तक चली जाती हैं। जो लोग इन योजनाओं को बनाते हैं वे ग्राम लोगों को दिक्कों को नहीं समझते। इसी कारण वे ऐसे लोगों से अबरदस्ती घन वसूल करने की बात करते हैं। मैं घाप से कहना चाहता हूं कि अगर माजूमों कीजिए तो सारा सामान सरकार खांदा, नहीं तो रीपुनर सेल व्यापार का चलते दें।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि खेती के काम को दो प्रकार के लोग करते हैं, एक किसान और दूसरे मेकेंटेरर्स में एरलंड, कन्ड कमरों में हैइने वाले बाबू। लेकिन किसान के दृष्टिकोण में और बाबू के दृष्टिकोण में बड़ा फर्क पड़ता है। वह फर्क इस तरह पड़ता है। अभी मैं घपने प्रवेश में गया था। एक तरफ तो प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि घन बढ़ाओं। मैं घापको बताता हूं कि इतना किसान घपने पूरा महलत से और घपने सारे साधन लगा कर पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन और किसान के पास जाकी शक्ति नहीं है जिसका उपयोग करके वह घापको ज्यादा घन दे सके। जो भी शक्ति, जो भी साधन सरकार के पास हैं, उन्हीं को दे कर सरकार पैदावार बढ़ा सकती है।

एक और तो सरकार कहती है कि अधिक घन पैदा किया जाय और दूसरी और प्लानिंग कमिशन की तरफ से एक बंधक को सहनाई बजती है। प्लानिंग कमिशन ने राज्य सरकारों को लिखा है कि पानी, बिजली और मगान की दर बढ़ाई जायें। घापने अभी देखा कि कस का टैक्टर, जो कि चौदह हांस पावर का है, छ हजार रुपये में बिकता था, लेकिन उसके दाम में बार हजार रुपय और बढ़ा दिये गए हैं। इस लिए धारणकता इस बात की है कि सरकार इस प्रकार की प्रत्याहारिक नीतियों को न घपनाये।

पानी के लिए माननीय सदस्य, शर्मा जी, ने बहुत और से कहा है। मैं उन के साथ सहमत हूं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में अंडक योजना एक सिवार्ड योजना है। राजन्दा बाबू जब खास मंत्री थे, तब उन्होंने उस को प्रारम्भ किया था। मरने से पहले राजेन्द्र बाबू ने प्रपत्ती प्रांशों में प्रसू भर के हमारे प्रदेश के मंत्री श्री दीप नारायण सिंह से कहा, "दीप बाबू, का हमरा जिन्वर्ग में अंडक योजना न बनी?" इस भावना को लिए वह बले गए। मैं समझता हूं कि दीप बाबू भी बसे जायेंगे, लेकिन अंडक योजना को कोई देख नहीं सकेगा।

अंडक योजना में कल्प 52 करोड़ रुपये लयेंगे और उस के द्वारा 2.50 करोड़ मज पैदावार यहाँ होगी। अंडक योजना सब में कम दाम में सब से ज्यादा लाभ देने वाली योजना है। मैं सिवार्ड विभाग से निवेदन करूंगा कि अंडक योजना को भी घ पूरा करने का प्रयास किया जाये। इस से नार्थ बिहार के मुजफ्फरपुर, जम्हारन, दरभंगा और सारन जिलों की कायदा हांगत, नेपाल की भूमि की सिफार्ड होगी और मोरमपुर और देवरिया को भी कायदा हांगत।

मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं। राजेन्द्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री थे। बिहार में कोई भी कृषि विश्वविद्यालय मुनिर्बसदी

[श्री एम० गेबबर प्रसाद सिंह]

नहीं है। इस लिए छतरा जिला में उन के जन्मस्थान में उनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। यह उन के प्रति श्रद्धाञ्जलि भी होगी और कृषि के काम में भी उत्पत्ति होगी। बूकिक कल उनका जन्मदिन है, इस लिए इस अवसर का लाभ उठा कर यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान कर दिया जाये।

Sbrl Kappes (Muvattupuzha):
Mr. Chairman, grim as the food situation today is, it has led to suggestions, amateurish suggestions, which if put into practice, would ruin this country. Following the broadcast by the Prime Minister on the food situation, many amateurish suggestions like diverting land from cash crops, ploughing up gardens and road margins for cultivation of vegetables have been put forward. It shows a confusion of thinking. In a crisis, it is bu. natural that there is some confusion. But we here who are responsible for formulating national policies should have clear thinking on these matters. Our thinking must be clear, constructive and divorced from all slogans and petty ideologies to which we are accustomed.

There is no purpose in finding fault w/b each other. On the other hand, the problem can be solved only by clear thinking and dynamic action. The Prime Minister has given us a slogan, 'Jai kisan, jai jawan'. This, according to me, epitomises in two words what our entire approach should be to the problem. In railway stations, I have found stalls being erected for catering to the jawans. But I was not able to see even one stall for the kisans. Here I am not pleading for atal's for the farmers. But I want this House and the country to have an awareness of the importance of the farmer in any programme of agricultural production. The difficulty in India about agricultural production is that it has to come from millions of tiny farms in the far-flung villages of India and during these 18 years we have not been able to reach the farmer pro-

perly and energise him and make him understand the necessity of producing more in this country. It is only by energising the farmer that we can succeed in any scheme of increased production.

I speak of energising the farmer, but why should the farmer alone make a sacrifice for the country? What are the benefits that he is going to derive? When it is a question of fixing the price for agricultural commodities, we forget that the farmer is also a person who consumes many of the commodities that are produced in the country, that the farmer is also entitled to share in the prosperity of the nation. When you want the farmer to use more fertilisers, better methods of cultivation, better instruments of production, you must remember that his cost of production is increasing thereby, and unless you are prepared to give a remunerative price to him and improve his social status, you are not going to succeed in your drive for more production. Give the farmer a better status, give him the assurance of a better remuneration, then you simply sit quiet here, and you will see that wonders are worked in this country. But we have never cared for the farmer, we have never understood that his cost of production is increasing, over and above the heavy taxes to which he is subject. He has to pay the betterment levy. If you have given him irrigation facilities, he has to pay the water cess. So, his cost is increased.

I am myself a farmer. I have got an acre of paddy land. I am producing one crop on that. I can produce probably one more crop, but then the cost will be double that of producing one. Who is going to pay me if I produce one more crop? The distribution officer will come and cut my ration by so much. If I am producing 100 measures today, he will collect 150 that is what is being done in Kerala today. Which farmer is going to produce more?

Again, my land is subject to submersion by floods and in summer it is subject to drought. Suppose I am

to produce another crop, that may be lost to me by either flood or drought. Who is going to pay me? What social benefits am I getting as a farmer? You are providing better and better social amenities to the Government employees and the organised factory labour, but to the farmer what social benefits are you giving? I would request the Government to immediately introduce crop insurance in this country so that the farmer may not be affected in case he loses his crop. The U.S.S.R., U.S.A., Japan and many other countries have introduced a scheme of crop insurance. This is an immediate necessity to give the farmer an assurance that in case of loss of his produce, he is going to get something. In that case, I assure you wonders will be worked by our farmers.

I do not want to speak about long-term programmes, it is not relevant in the context of the present emergency. I am just pointing out some crash programmes. I read through the pamphlet published by the Ministry of Food and Agriculture. In para 48 of that report it speaks about fisheries development. In a highly deficit State like Kerala, where all the land that is possible to be brought under cultivation has been brought under cultivation, the only possible method by which food can be increased is by production of subsidiary crops like tapioca and fish. We are now cultivating about 4.5 lakhs of acres with tapioca and by a little more manure and better methods of cultivation this crop can be doubled or even trebled, easily. Tapioca is deficient in protein; it cannot be eaten alone as it will produce diseases like beri, etc. Fish is rich in proteins. Tapioca, fish and rice would form a balanced diet. By an investment of Rs. 7-8 crores the present production of fish can be doubled or trebled. At present the production in Kerala of fish is about 3,10,000 tons. Of these 75,000 tons are exported to other States in India and 2,000 tons to foreign countries. If you could buy some trawlers for deep

sea fishing by an investment of about Rs. 3 crores, the present catch of fish can be increased by 1,42,000 tons. By mechanising 100,000 boats at a cost of about 4 crores, you can catch 80,000 tons more fish. By supplying fishermen with 1600 ordinary country boats you can produce another 60,000 tons. The total comes to 1,82,000 tons on an investment of Rs. 7-8 crores. Fish that is caught in the waters of Kerala are very much appreciated and valued in countries like the United States. It is estimated that on an investment of Rs. 3 crores on trawlers, the return will be Rs. 2,10,000 annually. This is a very good investment and I urge upon the Government to see that this is immediately put into practice so that their target of 1.94 million tons could be achieved. For want of time, I conclude my speech here.

श्री हुकुम चन्द्र कच्छवार: समाप्ति महोदय हमारे देश में अन्न का संकट है और इस विषय में हम दो दिनों से चर्चा करने वाले थे। मैं कहूँ तो लोगों ने अपनी विचार व्यक्त करने हुए बताया कि देश में अन्न का संकट है और कुछ ने जासन की वृत्ति बतलाई। किसी ने बताया कि पानी कम हुआ है। इस कारण से हमारे देश में अन्न की कमी पैदा हुई है। मैं यह बात मानता हूँ कि अन्नधान्य की कृषि इस वर्ष हमारे ऊपर ठीक नहीं रही और इस कारण से अन्न कम हुई तथा अन्नधान्य ज्यादा पैदा नहीं हो पाया। फिर भी हम को बाहिये कि हम इस स्थिति पर विचार करें।

आज हम इस बात का नारा देते हैं, विशेषकर जो हमारा देश है वह कहता है कि तुम हमें पानी दो, हम तुमको अन्न देंगे। हमारी धमिल में बहुत सा पानी है। अगर वह हम को ठीक प्रकार से मिलता है तो हम तुम को अन्न दे सकते हैं। काकाकार भी बही कहता है कि हमें पानी बाहिये, हम तुम को अन्न दे सकते हैं। लेकिन पानी के लिये एक कृषिकारी सम्बन्धित होना बाहिये, इस सरकार को बहुत समय से और ज्यादा ध्यान दे कर इस और

[श्री हुसैन बख्श कलवाय]

कम बढ़ाने चाहिये। सिचाई के लिये ट्यूबवैलों और छोटे छोटे कुएँ खोदने की योजनाएँ होनी चाहिये, जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त सके।

घायको उता होगा कि अभी अब देश पर संकट धाया, पाकिस्तान ने वाकमज किया दिल्ली के अन्दर प्राफिटियरिन की जो सारी समस्याएँ जन संघ के कार्यकर्ताओं ने उसे हल किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम जन संघ के कार्यकर्ता घायको देते हैं। घाय हुसैनको पानी दीजिए हम घायको काफी तादाद में अन्न पैदा करके देंगे। मैंने अनेक बार रेसले मंत्री से अन्नमन्त्रालय पूछे कि रेसले की पटरियों के पास जो हवाराएँ एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई हैं जहाँ पर हम अन्न पैदा कर सकते हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। हमें अनेक बार अन्नमन्त्रालय दिया गया कि हम किबाब करेंगे, हम बिबाब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रेसले की पटरियों के पास जो खाली भूमि है वहाँ हम अन्न पैदा करें। अब समय था गया है कि हम इस घोर कष्ट बढ़ाये और अन्न ज्यादा पैदा करें।

अब तक किसानों का सम्बन्ध है किसानों को ज्यादा सहयोग चाहिये, उनको ज्यादा प्रोत्साहन और सहायता मिलनी चाहिये। अगर उन्हें ज्यादा बढ़ावा दिया जाये तो किसान ज्यादा तादाद में परिश्रम और मेहनत करके अपने काम को करने और देश में जो अन्न संकट छाया हुआ है उसको दूर करेंगे। हमने देखा कि, काश्तकार से अब अन्नान्त लिया जाता है तो उसे बहुत कम दामों में लिया जाता है, लेकिन अब वही काश्तकार अपने बाजार में अन्नान्त लेने के लिये जाता है तो उसे काफ़ी दाम देने पड़ते हैं। काश्तकार को ईमानदारी से अन्न का दूरा दाय मिलना चाहिये। उसके काम में पाने वाली जो बीजें हैं, चाणेनीय का साबान हो या दूसरा सामान हो, उसे सस्ते दामों पर मिलनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि काश्तकार जो पान बहुत सी बातों में खानाकानी करते हैं

यह इस कारण से है कि उसके साथ भेदभाव करता जाता है और पलपात किया जाता है। इन सारे कामों में उसकी समस्याओं हल हो जायेंगी।

आज जनता से कहा जाता है कि अन्न देश में पाने की कमी है इसलिये मैंने ज़ुबान खाना चाहिये। ठीक है, लेकिन मांस किसका खाना चाहिये। मांस की नशा खाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ कि घाय बम्बई बन्दरगाह को देखिये। वहाँ बोमार जानवरों को काटा जाता है और उनका मांस लोगों को खाने को दिया जाता है। जो कि बोमार पशु होते हैं जिनसे बीमारी बढ़ती है उनकी घोर ध्यान रखा जाना चाहिये क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो देश में बीमारी फैलेगी। मैं यह नहीं कहता कि घाय लोगों को मांस खाने को मन धोजिये क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अभी हमारे एकामत्र कह रहे थे कि मछली का उत्पादन कराने में होता है। मैं कहता हूँ कि जहाँ मछली का उत्पादन हो सकता है वहाँ उद्योग करना चाहिये, लेकिन जिन प्रदेशों में नहीं हो सकता है वहाँ पर ताखी रूप से खर्च करने पर भी नहीं होगा। घाय क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जहाँ पर होता है वहाँ कीजिए। घायने एक प्रास्तावक बताया कि मछली पालना, मत्स्य पालना, मर्गी पालना। इसका विरोध नहीं करना लेकिन घायको देना चाहिये कि यह कहा जा सकता है घाय घाय किस्त बंध की आवश्यकता है।

हम देखते हैं कि बहुत सी सड़कों पर अन्नक प्रकार के पेड़ होते हैं, लेकिन जो पेड़ फल दे सकते हैं उनसे पैद की कुछ मिट सकती है। घायको ऐसे पेड़ वहाँ लगाने चाहिये जिनके परबर्षा करने में ज्यादा समय न लगे। यदि हम ऐसे पेड़ों को लगायेंगे तो सम्भव है कि उनके फल हमारे काम में पासके।

कभी कभी कहा जाता है कि मांस खाना मर रहे हैं। इसको मुन कर मुझे उठाया

का एक किस्मा याद घाता है । वहां कुछ लोग भूख से मर गये । डाक्टर कहता है कि नहीं भूख से नहीं मरे । कैसे मरे । इसलिये मरे कि उनके पेट में दर्द था । दर्द क्यों हुआ । इसलिये कि धाम की गुठली खा ली थी । क्यों गुठली खा ली थी । इसलिये कि भूखों मर रहे थे । भूख क्यों लगी । यह पता नहीं । घनाज खाने को नहीं मिला इसलिये उन लोगों ने धाम की गुठली खाई और गुठली के खाने से पेट में दर्द हुआ । मैं बनसाना चाहता हूँ कि हम लोग रेन में सफर करते हैं तो जो धाम खा कर फेंक देते हैं, उन के छिलके को लांग चूसते हुए दिखाई पड़ते हैं । यह हमारे देश की दशा है । इस सम्बन्ध में बहुत से लोग यह कहने के शौकीन हैं कि हमारा देश भूखा है । इस का प्रचार खूब होता है । मैं कहना चाहता हूँ कि हम घर में भूखे रह लेंगे लेकिन इसके लिये हमको विदेशों में नहीं जाना चाहिये । यह बहुत बड़ा कर्त्तक है हमारे लिये कि हम किसी में जा कर कहें कि हम भूखे हैं । यह बहुत बुरी बात है । हम भूखे ज़रूर हैं लेकिन इस के लिये हमको दूसरे देशों के मामले हाथ नहीं पसारना चाहिये । हम भूखे रहेंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ । हम एक समय खावेंगे एक दिन में, दो दिन में एक समय खावेंगे लेकिन रहेंगे स्वाभिमान के साथ ।

घाज देश को नारा दिया गया कि कम खाना चाहिये । सबसे पहले देश के धन्द्वर भारतीय जनसंघ ने नारा दिया कि हम हर मंगलवार को भोजन नहीं करेंगे क्योंकि इससे देश में भोजन बचेगा । हम उस घनाज को जहाँ घनाज की कमी है वहाँ भेजेंगे । लेकिन हमने देखा है कि यहाँ ससद् सदस्य बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाते हैं । सभापति महोदय, मुझे भी जाने का अवसर मिला । मैंने देखा कि वह अपने प्लेट में लेते कितना हैं और उसमें से खाते कितना हैं और फेंकते कितना हैं । हम बड़े आदर्श की बात करते हैं कि हमें भूखा रहना है लेकिन धाप पहले इस बात का धन्दाजा लगाए कि देश के धन्द्वर कितना लोग

झूठा फेंकते हैं और झूठा फेंकता कौन है? बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े धफसर, ऊंची तनखाह पाने वाले जो अपने धापको बहुत बड़ा मानते हैं, ऐसे लोगों के घरों में काफी झूठन फेंकी जाती है । उसका धन्दाजा लगाया जाय तो लाखों टन का हिसाब बैठेगा । तो हमें इसका प्रचार करना चाहिए कि लोग अपनी घाली में उतना ही लेबे जितना खा सकें । मिट्टी की तरह उसे फेंका न जाय । घाज जनता कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, मैंने देखा घाज जब वह घनाज लेने जाते हैं दूकान पर तो उन्हें कितनी परेशानी होती है । यह हो सकता है कि हमारे बांटने की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था ठीक न हो परन्तु लोगों में कितना भय फैला हुआ है, वह सोचते हैं कि हमें मिलेगा या नहीं । सभापति महोदय, मैंने स्वयं अपनी घाखों देखा है उज्जैन के धन्द्वर कि रात को मिल में काम करके 12 बजे मजदूर घाता या और उसके बाद राशन की दूकान पर जाकर 12 बजे से लाइन लगाता था जबकि दूकान 8 बजे खुलती है, 8 घंटे लाइन में वह खड़ा रहता था, तब उसको घनाज मिलता था । कितनी परेशानी उसमें होती है । सरकारी कर्मचारी क्यू में लाइन लगाकर खड़ा होगा या नौकरी पर जायगा ? यहाँ एक उत्तर में कहा गया कि हमने कुछ दूकानें खोली हैं जहाँ से कि सरकारी कर्मचारी को सुविधा में घनाज मिल सके । मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने सरकारी कर्मचारी दिस्सी में हैं और कितनों को सहूलियत से घनाज मिलता है या जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उनमें काम करने वाले कितने लोगों को सहूलियत से घनाज मिलता है ? तो इसकी व्यवस्था की जाय कि उन्हें बिना किसी कठिनाई के घनाज मिले ताकि वह अपनी नौकरी पर ठीक समय पर जा पायें । घाज सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा यह पुकार है देश की, जनता चाहती है देश की । धापने जो जोन प्रचाचलायी है इसे समाप्त किया जाय क्योंकि जो प्रान्त ज्यादा पैदा करते हैं वह रख कर बैठ जाते हैं, पड़ोस का कोई प्रान्त है, वहाँ घनाज

[श्री हुकम चन्द कल्लवाय]

ज्यादा पैदा नहीं होता है, दूसरी चीजें पैदा होती हैं, वहाँ नहीं भेजा जाता यह जो प्रानप्रवा है खरम करनी चाहिए। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 30 रुपये मन गेहूँ मिलता है, वही पौरी से महाराष्ट्र में ले जाया जाय तो शीक से 80 रुपये मन बेच सकते हैं। तो इससे घुंटाघार बढ़ता है और लोगों को ज्यादा धनिक करने का अवसर मिलता है। मैं इसका धोर विरोध करता हूँ और यह जो प्रथा है खरम करनी चाहिए।

काफी लोगों ने यह बात कही है कि कहां तक ऐसी दशा है। मेरे पास घाज ही उज्जैन से एक तार आया है जहां का मैं निवासी हूँ। उन्होंने लिखा है—उज्जैन में नवम्बर माह में तथा दिसम्बर में पर हेड एक किलो देसी धीर विदेशी गहूँ नहीं मिल पाता। चावल की हालत बहुत चिन्ताजनक है और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टरेट है वह इनकी व्यवस्था नहीं कर पाता है। मैं पूछता हूँ कि घाखिर यह क्या है? ऐसी दशा क्यों है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि घाज जो बहुत सी जमीन फालतू पड़ी है वहां पर हमारी सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, एक फौज तैयार करनी चाहिए, एक सेना तैयार करनी चाहिए। किस बात के लिए कि जहां खाली जमीन पड़ी है, लाखों एकड़ भूमि पड़ी है वहां जाकर खेती करे, घाज पैदा करे, यह सरकार का कार्यक्रम होना चाहिए। एक धोर सरकार कहती है कि हमें ज्यादा घनाज पैदा करना चाहिए, मैं सभापति महोदय, घाजके द्वारा सरकार से बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारे रामचन्द्र बड़े बिट्ठल के

क्षेत्र में जहां घादिवासी लोग रहते हैं, उन घादिवासियों का एक लाख रुपये का खर्चा घनाज, खड़ी फसल काटी गयी, मिट्टी में मिल गई। तो यह दोनों बातें कैसे चलेंगी? एक धोर कहते हैं घनाज ज्यादा पैदा करो, दूसरी धोर खड़ी फसल मिट्टी में मिलाना चाहते हो, यह दोनों बातें नहीं चलेंगी, न जनता यह बातें सहन कर सकती है। मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, घपनी बात की घन्त की धोर ले जाते हुए कि सरकार ऐसी नीति घपनाये जिससे देश के घन्दर काफी ज्यादा लोग घन्न पैदा कर सकें, लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले। लेकिन जो प्रान्त प्रान्त के घन्दर घलग घलग कानून है, मध्य प्रदेश में कुछ है, उत्तर प्रदेश में कुछ है, पंजाब में कुछ है, यह क्या है? हमारी एक नीति होनी चाहिए, एक पालिसी होनी चाहिए, सारे देश के घन्दर उसी के मुताबिक वह कानून लागू होना चाहिए और फिर घमल करना चाहिए। घापने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बड़ा घाभारी हूँ और मैंने जो मुझाव दिये, सरकार उन पर ध्यान देगी।

Mr. Chairman: Shri K. L. More.

Shri K. L. More (Hatakanangle):
Mr. Chairman, Sir.....

Mr. Chairman: The hon. Member may continue his speech the next day.

18-56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 3, 1965/Agrahayana 12, 1887 (Saka).